टाइटल कोड - MPHIN37675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

संपादक - विवेक जैन

वर्ष 01 अंक 09 | नवम्बर 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

रबी फसलों की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद : मंत्रालय

अब तक 54 हजार हेक्टेयर में गेहूं, 18 लाख हेक्टेयर में की गई सरसों की बुवाई

हलधर किसान। (विवेक जैन, 98262 25025) खरीफ फसलों की कटाई के बाद अब किसानों ने रबी सीजन की तैयारी शुरु कर दी है। कई राज्यों में गेहूं, चना, सरसो आदि फसलों की बुआई भी हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022.23 के चालू रबी सीजन में अब तक 54 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई है।

यह पिछले साल की अवधि तक बोए गए गेहूं के 34 हजार हेक्टेयर के रकबे से 59 प्रतिशत अधिक है। 29 अक्टूबर को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रबी सीजन में अब तक 54 हजार हेक्टेयर में गेहूं और लगभग 18 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई की जा चुकी है। मुख्य रबी फसल गेहूं की बुवाई प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल तक फसल सूखकर तैयार हो जाती है। इसके अतिरिक्त चना, जौं, आलू, सरसों रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं।

रबी बुवाई में उत्तर भारत की स्थिति

उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा में रबी फसलों की बुवाई चल रही है। नये आंकड़े बताते हैं कि 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में लगभग 39 हजार हेक्टेयर, उत्तराखंड के 9 हजार हेक्टेयर, राजस्थान में 2 हजार हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 1 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की जा चुकी है। दलहन की बुवाई का रकबा इस रबी सीजन में 8.82 लाख हेक्टेयर हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि तक दलहन फसलों का रकबा 5.91 लाख हेक्टेयर था। हालांकि दलहन में चना एक साल पहले इस अवधि तक 5.91 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 6.96 लाख हेक्टेयर में लगाया गया था।

19.96 लाख हेक्टेयर में की गई बुवाई

तिलहन के आंकड़े बताते हैं कि चालू सीजन में छः प्रकार की तिलहनी फसलों की 19.96 लाख हेक्टेयर के रकबे में बुवाई की गई है। तिलहनी फसलों का रकबा पिछले सीजन की इस अवधि तक 15.13 लाख हेक्टेयर थाण्केवल सरसों की बात करें तो अब तक लगभग 18 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी हैण्पिछले वर्ष की अवधि तक सरसों की बुवाई का आंकड़ा 14.21 लाख हेक्टेयर था।

खरगोन जिले में 3 लाख 56 हजार 620 हेक्टेयर रखा लक्ष्य

इस बार मानसून में औसत से अधिक बारिश होने से किसानों को रबी सीजन में बंपर उत्पादन की आस बंधी है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने भी रबी फसलों के बुआई का प्रस्तावित लक्ष्य बढ़ाकर रखा है। खरगोन जिले में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चने में करीब 27 हजार हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। कुल लक्ष्य 3 लाख 56 हजार 620 हेक्टेयर रखा गया है, जो गत वर्ष के मुकाबले 3 हजार हेक्टेयर अधिक है। खाद. बीज की व्यवस्था में कृषि विभाग जुटा है। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस साल जिले में 2 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं, 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर में चना, गत वर्ष चना 1 लाख 14 हजार 340 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया था। मक्का 5 हजार हेक्टेयर में, मटर 10 हेक्टेयर खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि अधिकारी प्रकाश ठाकुर ने बताया कि रबी फसलों की बुवाई के लिए खेतों की जुताई करके पाटा लगाएं, जिससे मिट्टी की नमी कायम रहे। रबी फसलों की बुवाई के लिए खेतों को साफसुथरा, जल निकासी की व्यवस्था और मेड़ बनाने की सलाह भी दी है। मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए गोबर की खाद खेतों में फैलाएं। इससे मिट्टी में जीवांश बढ़ेंगे और बीजों का जमाव भी बेहतर ढंग से होगा। जिले के दुकानदार अब रबी फसल की खेती के लिए बाहर से बीज मंगाना शुरू कर दिए हैं। बीज व्यवसायियों के अनुसार चना, गेहूं, मटर, सरसो, मसूर, प्याज व अन्य दलहन तथा तिलहन फसल के बीज का आर्डर दिए हैं।

बुवाई में तेजी आने की उम्मीद

चालू रबी सीजन में 28 अक्टूबर तक सभी फसलों का कुल रकबा 37.75 लाख हेक्टेयर है। जो एक साल पहले की अवधि तक 27.24 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय का कहना है कि खरीफफसलों की कटाई के बाद आने वाले हफ्तों में रबी फसलों की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर में हुई बुवाई, त्योहारों के चलते धीमी बुआई

रबी सीजन में त्यौहारों के कारण फसलों की बुवाई धीमी गति से चल रही है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है। प्रदेश में खरीफफसलों की कटाई में देरी की वजह से रबी की रफ्तार कम हुई है। वैसे इस वर्ष पर्याप्त नमी के कारण बेहतर उत्पादन की संभावना है। 28 अक्टूबर तक मण्प्रण् में 10.43 लाख हे.में बुवाई हुई है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 9ण्21 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई थी। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107 लाख 33 हजार हेक्टेयर है।इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी।

कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 10.43 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 1.72 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि गत वर्ष अब तक 0ण्62 लाख हेण् में गेहूं बोया गया था।दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 2.25 लाख हेक्टेयर में हो गई है जो गत वर्ष समान अवधि में 2.99 लाख हे.में हुई थी। अन्य फसलों में अब तक मटर 69 हजार हे. , मसूर 85 हजार हे. में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी 4.70 लाख हे. में हुई है जबकि इस वर्ष 13.07 लाख हे. लक्ष्य रखा गया है। वहीं अलसी की बोनी 16 हजार हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष गन्ना 1.40 लाख हेक्टेयर में लिया जायेगा, बुवाई की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 1.78 लाख हे. में, दलहनी फसलें 3. 78 लाख हे. में एवं तिलहनी फसलें 4.86 लाख हे. में बोई गई हैं।

फसल	लक्ष्य	बुवाई
गेहूं	89.03	1.72
जौ	0.52	0.06
चना	24.47	2.25
मटर	2.8	0.69
मसूर	6.49	0.85
सरसों	13.07	4.7
अलसी	1.27	0.16
गन्ना	1.4	0.01

नागरिक रैलियां निकाल कर रहे प्रदर्शन

न्यूजीलैंड में गायों की डकार पर लगा टैक्स!

हलधर किसान इंटरनेशनल डेस्क। 98262 25025

न्यूजीलैंड में गायों की डकार और अन्य ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन पर कर लगाने की सरकार की योजना के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए। न्यूजीलैंड में गायों की डकार ने एक नयी तरह की समस्या पैदा कर दी है। इस पर सरकार की प्रस्तावित टैक्स योजना के खिलाफकिसान सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में पिछले सप्ताह सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना के तहत नया कृषि कर लगाने का प्रस्ताव रखा। किसानों को अपने पशुओं से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए टैक्स चुकाना पड़ेगा। सरकार की प्रस्तावित योजना के खिलापकिसानों ने विरोध.प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी किसान सड़कों पर ट्रैक्टर और खेतों में इस्तेमाल होने गाड़ियों के काफिले के साथ सड़कों पर उतरे। वे सरकार से इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 2025 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन पर टैक्स लगाएगा। इसमें गायों और भेड़ों की डकारों से निकलने वाली मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन भी शामिल है। ये दोनों पर्यावरण के लिए एक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस हैं।

क्या है सरकार की योजना ?

न्यूजीलैंड में कृषि से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। देश की आबादी करीब 50 लाख है लेकिन इसकी तुलना में यहां एक करोड़ से ज्यादा गाय और भैंसें हैं और 2.6 करोड़ भेड़ें हैं। न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने और 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए दुनिया की पहली ऐसी किसी योजना की घोषणा की। सरकार ने 2030 तक 2017 के अपने मीथेन उत्सर्जन स्तर में 10 फीसदी कमी का प्रण लिया है, लेकिन किसानों के विरोध ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। सरकार का कहना है कि वह बातचीत के जरिये इस मामले को सुलझाने में जुटी है।

क्या चाहते हैं किसान ?

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि इस योजना से उनके रोजगार को नुकसान पहुंचेगा और भोजन ज्यादा महंगा हो जाएगा। प्रदर्शन करने वाले किसानों के समूहों में से एक ग्राउंड्सवेल के ब्राइस मैकेंजी ने सरकारी प्रसारक रेडियो न्यूजीलैंड से बातचीत में योजना को दंडात्मक और ग्रामीण समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा कहा. न्यूजीलैंड हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की संख्या आयोजकों की अपेक्षा से कम थी। प्रधानमंत्री जसिंदा अर्डर्न ने तर्क दिया है कि अगर वे जलवायु.अनुकूल उत्पादों के लिए कीमतें बढ़ाती हैं तो योजना किसानों को फायदा पहुंचा सकती है।उन्होंने ऑकलैंड में संवाददाताओं से एक बातचीत में कहा, हम अपने किसानों ओर खाद्य उत्पादकों से सबसे बेहतर संभावित तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। ब्राइस मैकेंजी कहते हैं, किसान सीधे.सीधे छूट की मांग नहीं कर रहे हैं। ग्राऊंड्सवेल न्यूजीलैंड समूह की मदद से देशभर के कस्बों और शहरों में 5 से अधिक जगह विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

किसान नहीं कर पाएंगे ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, हलधर किसान। भारत सरकार ने इंसान और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधित खतरों को देखते हुए हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे कई तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। एग्रो.केमिकल फेडरेशन ऑफइंडिया ने इस संबंध में किए गए वैश्विक अध्ययन और नियामक निकायों का हवाला देते हुए इस फैसले का विरोध किया है। कहा है कि इस तरह किसान इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

ग्लाइफोसेट और इसके फॉर्मूलेशन व्यापक रूप से पंजीकृत हैं। मौजूदा समय यूरोपीय संघ और अमेरिका समेत 160 से अधिक देशों में इसका इस्तेमाल होता है। दुनियाभर के किसान 40 से अधिक साल से सुरक्षित और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि ग्लाइफोसेट का उपयोग प्रतिबंधित है। कीट नियंत्रण परिचालकों ;को छोड़कर कोई भी इसका उपयोग नहीं करेगा। कंपनियों को ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंजीकरण समिति को वापस करने के लिए कहा गया हैए ताकि लेबल और पत्रक पर बड़े अक्षरों में चेतावनी को शामिल किया जा सके। इसमें कहा गया है कि पीसीओ के माध्यम से ग्लाइफोसेट फॉर्मूलेशन के लिए अनुमति दी जाएगी।

कंपनियों पर होगी कार्रवाई

कंपनियों को प्रमाणपत्र वापस करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, अन्यथा कीटनाशक अधिनियमए 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित करने वाली अंतिम अधिसूचना दो जुलाई, 2020 को मंत्रालय द्वारा एक मसौदा जारी किए जाने के दो साल बाद आई है। इस खरपतवार नाशक के वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए केरल सरकार की एक रिपोर्ट के बाद मसौदा जारी किया गया था।

किसानों को असुविधा होगी

सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए एग्रो.केमिकल फेडरेशन ऑफइंडिया के महानिदेशक कल्याण गोस्वामी ने कहा. ग्लाइफोसेट आधारित फॉर्मूलेशन उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं। भारत समेत दुनियाभर में अग्रणी नियामक प्राधिकरणों द्वारा इसका परीक्षण और सत्यापन किया गया है। केवल पीसीओ के माध्यम से ग्लाइफोसेट के उपयोग को सीमित करने का कोई तर्क नहीं है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उपस्थिति नहीं है। इससे किसानों को असुविधा होगी और खेती की लागत भी बढ़ेगी।

ग्लाइफोसेट का उपयोग कृषि क्षेत्रों से सभी प्रकार के खरपतवारों को साफकरने के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख खपत बागों और बागान फसलों में की जाती है। ग्लाइफोसेट का सबसे अधिक उपयोग अंगूर, चाय, कपास, आम बाग के किसान करते हैं।

क्या आप अपना
खुद का व्यापार स्थापित
करना चाहते है ?

मध्य भारत की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन
आउटलेट बीज भंडार की फ्रेंचाइजी ले
और बने अपनी दुकान के मालिक

बीज भण्डार™

बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करे।
बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन मोबा. 8305103633

उन्नत खेती के उत्तम बीज

कृषि मशीनीकरण और सरकारी योजनाएं

संपादकीय...

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। विश्व बैंक की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रामीण लोगों की आबादी लगभग 65.97 प्रतिशत है। भारत के गांवों में रहने वाले ये लोग आज भी मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं।

भारत में प्राचीनकाल में परंपरागत रूप से कृषि कार्य होता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास ने खेती के स्वरूप को बदल दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय किसान खेती करने के लिए परंपरागत और अकुशल औजारों के स्थान पर नए और विकसित कृषि यंत्रों जैसे खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर, बिजली से चलने वाले सिंचाई यंत्र, फसल काटने के लिए हारवेस्टर्स जैसी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। इससे उत्पादकता पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी है।भारत में पहले से ही खेती बैल, अन्य जानवरों या मानव श्रम द्वारा की जाती रही है, लेकिन मशीनीकरण ने खेती को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कृषि भूमि पर मशीन शक्ति के प्रयोग को दर्शाता है। साधारण शब्दों में कहें तो मशीनीकरण वह प्रि या है, जिसमें मनुष्य या पशुओं की सहायता से किए जाने वाले कार्य को मशीनों द्वारा किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कृषि मशीनीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का एक महत्वूर्ण तत्व है।

गौरतलब है कि भारत के कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विस्तार और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से वर्ष 2014.15 में कृषि में मशीनीकरण के उप.मिशन स्माम योजना की शुरुआत की गई है। यह उप.मिशन कृषि के सतत विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, परीक्षण, कृषि मशीनरी ख़रीद सब्सिडी के पारंपरिक घटकों को शामिल करते हुए उच्च तकनीक आधारित उच्च उत्पादक उपकरण केंद्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में भारत में कुल कृषि मशीनीकरण लगभग 40.45 प्रतिशत ही है। वहीं, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां कृषि मशीनीकरण 95 प्रतिशत, ब्राज़ील में 75 प्रतिशत और चीन में 57 प्रतिशत है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कई बड़े देशों के मुकाबले भारत में कृषि मशीनीकरण अभी भी काफी कम है। केंद्रीय बजट 2020 से एक दिन पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि भूमि, जल संसाधन और मज़दूरों में कमी आने की वजह से कृषि में उत्पादन और कटाई के बाद के कार्यों की जिम्मेदारी मशीनीकरण पर ही टिकी हुई है। ऐसे में सर्वे के आधार पर रिपोर्ट में सरकार से कृषि मशीनीकरण को और बढ़ाने के लिए कहा गया।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि बिजली और उत्पादन का सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने खाद्यान्न की बढ़ती मांग से निपटने के लिए 2030 के अंत तक 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर 2016.17, से 4.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक बिजली की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है।

मशनरी के नुकसान-कृषि में मशीनीकरण केवल बड़े आकार के खेतों के लिए ही कारगर है, जबकि यह छोटे आकार के जोतों के लिये वित्तीय भार बढ़ाने का काम करता है। इससे इनपुट की तुलना में कम आउटपुट मिलता है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिए जाने की वजह से भारत जैसे देशों में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ी है, क्योंकि इससे कृषि कार्यों में मानवीय संलग्नता काफ़ी कम हो गई है। मशीनीकरण से पर्यावरण प्रदूषण में इज़ाफा हुआ है, क्योंकि किसान खेतों को जल्दी खाली करने के लिये पराली जलाने लगे हैं। हालांकि, कृषि में मशीनीकरण के कुछ नुकसान हैं, फिर भी छोटे तथा सीमांत किसानों और बड़े किसानों के बीच समन्वय स्थापित कर कृषि में मशीनीकरण समय की मांग है। जिससे भारतीय परिदृश्य में खेती.किसानी को 'घाटे का सौदा' जैसे संबोधन से उबारा जा सकता है।

इंजीनियर पति-पत्नी का कमाल

किसानों की मदद के लिए बनाया इलेक्ट्रिक बैल

हलधर किसान।
(98262 25025)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जंहा पहले बैलो से खेती की जाती थी, तो उसकी जगह ट्रेक्टर ने ले ली। खेतो में जुताई.बुआई अब भी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया है। और इसी बदलते दौर की जरूरत को समझा एक इंजीनियर दंपत्ति ने और बना दिया इलेक्ट्रिक बैल। जी हां, हांड मांस का बैल नहीं इलेक्ट्रिक बैल। जिसकी मदद से किसान कई सारे काम आसानी से कम लागत में करके अच्छी आमदनी का लाभ उठा सकते है।

पेशे से इंजीनियर तुकाराम सोनवने और उनकी पत्नी सोनाली वेलजाली ने बताया देशभर में फैली महामारी के चलते, लॉक डाउन के उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला। हम लोग भी पुणे से अपने गांव आ गए। 14 सालों में शायद पहली बार ये दोनों लोग अपने गांव अंदरसुल में इतने ज्यादा समय तक रुके। इससे पहले दोनों गांव त्योहारों की छुट्टियों पर आते थे और वापिस चले जाते थे।। लेकिन महामारी ने सब बदल दिया और दम्पत्ति को गांव में रुकना पड़ा। लेकिन यह एक मौके की तरह साबित हुआ, जिसमें किसानो की तकदीर बदलने वाला फैसला हुआ।

तुकाराम पेशे से मकैनिकल इंजिनियर हैं, उन्होंने गांव के पुराने मित्रो और परिचितों से लंबी मुलाकाते की तो जाना कि देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उनका गांव अभी भी पुरानी पद्धति पर खेती के लिए मवेशियों और श्रम पर निर्भर है। जिसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा था। खासकर छोटे और मझले किसानो की खेती लागत बढ़ रही थी, और आमदनी घटने की बजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता था। जिसका मुख्य कारण मशीन का इस्तेमाल न के बराबर करना था।

किसानों की मदद के लिए बनाया

तुकाराम ने अपनी पत्नी सोनाली जो पेशे से एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक बुल बनाने का फैसला किया। जो खेतों की जुताई.बुवाई और कीटनाशक के छिड़काव की प्रक्रिया में बहुत अधिक श्रम लगता है, उसको कम करने में सक्षम है। तुकाराम और सोनाली का मानना है कि इससे किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों को काफी मदद मिलेगी।

तुकाराम के मुताबिक इलेक्ट्रिक बुल सामान्य मवेशी की तुलना में सिर्फ1 0 पैसे खर्च करता है और सारी प्रक्रिया ठीक से करता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बुल के निर्माण के लिए इंजन और अन्य सामग्रियां बाहर से मंगवाई गई है। जिसके बाद हमने एक ऐसी मशीन बनाने के लिए दिन.रात एक कर दिया, जो सभी काम प्रभावी ढंग से करे।

क्या-क्या काम कर लेता है इलेक्ट्रिक बुल

महीनों तक किसानों की समस्या पर रिसर्च करने के बाद तुकाराम ने इस इलेक्ट्रिक बैल का निर्माण किया। एक बार जब खेत जुताई के बाद तैयार हो जाता है और पहली बारिश होती है तो इलेक्ट्रिक बुल वहीं से लेकर कटाई तक सभी काम का ध्यान रख सकती है। तुकाराम का इलेक्ट्रिक बुल बिना एक्सेल का एक वाहन है जो खेती में अलग.अलग तरह के काम कर सकता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने कृषिगति प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक स्टार्टअप भी शुरु किया है। वही सोनाली ने बताया कि लगभग 2 एकड़ जमीन के पारंपरिक रख.रखाव में करीब 50.000 रुपये लगते हैं। लेकिन इस उपकरण से केवल 5.000 रुपये में काम हो जाता है। इस तरह, लागत घटकर 1/10 हो जाती है। सोनाली का कहना है कि प्रोडक्ट का उत्पादन चल रहा है और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा।

मशीन ट्रायल में भी हुई पास

एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक बुल चार घंटे तक काम करता है। सोनाली बताती हैं कि, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का ज्यादा प्रचार नहीं किया है, लेकिन उनके इनोवेटिव मशीन की मांग पहले से ही होने लगी है। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों और कंपनियों ने हमसे पूछताछ की है। अब तक, हमें लगभग 300 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और दस ग्राहकों ने मशीन बुक कर ली है। लगभग सात डीलरों के साथ बातचीत चल रही है।

एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक बुल चार घंटे तक काम करता है।

जमीन के पारंपरिक तरीके से रख.रखाव में पर 50.000 रुपए लगते है। इस उपकरण से केवल 5.000 में काम हो जाता है।

लागत घटकर 1/10 हो जाती है। इसके अलावा सिंगल फेज इकाई पर सिर्फ2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है।

ये प्रोडक्ट अपने सेगमेंट में पहला एक्सल.लेस वाहन है, जो सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलों और चुनिंदा सब्जियों में इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकता है।

इससे समय और लागत की बचत होती है और इसे चलाने के लिए एक ही व्यक्ति की जरूरत होती

कांगेर घाटी के जंगलों में फिर से दिखेगा चीतलों का झुंड, प्रजनन केंद्र से छोड़े 52 चीतल

हलधर किसान।98262 25025
छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क से 52 चीतलों को जंगल में छोड़ा गया है। इन सभी चीतलों को विभाग ने कुछ साल पहले प्रजनन केंद्र में रखा था, जहां ये चीतल पले बढ़े जिसके बाद अब सभी चीतलों को जंगल में छोड़ दिया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों का मानना है कि अब बस्तर के जंगलों में एक बार फिर चीतलों की झुंड दिखाई देगी और खुले जंगल में रहने से इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ेगी। इसके साथ ही मांसाहारी जानवर भी इसी जंगल को स्थायी ठिकाना बनाएंगे, यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में चीतलों को जंगलों में छोड़ा गया है। इधर कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतलों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।

बस्तर के वाइल्ड लाइफसीसीएफए के श्रीवास्तव ने बताया कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में शाकाहारी पशु, पक्षी और मगरमच्छ बड़ी तादाद में है लेकिन विभाग के द्वारा मांसाहारी जानवरों का भी पता लगाया जा रहा है। कुछ साल पहले कांगेर घाटी के राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों की देखने की भी पुष्टि हुई थी, लेकिन बड़े क्षेत्र में फैले कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में कुछ महीनों से मांसाहारी जंगली जानवरों को नहीं देखा गया है। डियर पार्क के अंदर ही चीतलों के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, जहां कुछ साल पहले बाहर से चीतलो को लाकर इस प्रजनन केंद्र में रखा गया थाए अब इन सभी चीतलों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। चीतलों की संख्या में नजर बनाए रखे हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि चीतलों को जंगल में छोड़ने बेहोश नहीं किया गया, इसके लिए बोमा तकनीक अपनाई गई। इसके तहत गुफा नुमा एक ढांचा खड़ा किया गया। दूसरे

छोर से सटाकर गाड़ी रखी और रैंप बनाया और गुफा के मुख्य द्वार से गाड़ी तक खाने का सामान रखा गयाए चीतल खाते.खाते रैंप से गाड़ियों में पहुंचे फिर उन्हें जंगलो में छोड़ा गया, विभाग के सभी कर्मचारी चीतलों की संख्या में नजर बनाए रखे हुए हैं और इधर कांगेर वैली के खुले जंगल में अब पर्यटक भी आसानी से चीतल देख सकते हैं। वाईल्ड लाइफ सीसीएफ ने बताया कि इन चीतलों का मानवी शिकार ना हो इसके लिए भी खास सुरक्षा बरती जा रही है। इसके साथ ही उद्यान में मांसाहारी जानवरों की वर्तमान स्थिति और संख्या के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

चीतों के बाद मध्यप्रदेश में अब जल्द लाए जायेगें हाथी, करेंगे वन्यप्राणियों की सुरक्षा

हलधर किसान।टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट के बाद मध्यप्रदेश अब एलिफेंट स्टेट बनने जा रहा है। जी हां मध्यप्रदेश में हाल ही में चीता स्टेट बनने के बाद कर्नाटक के हाथी लाए जा रहे हैं। 15 हाथियों को वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है। यह हाथी अगले माह तक मध्यप्रदेश के जंगलों में पहुंच जाएंगे। अगले महीने नवंबर में हाथी मध्यप्रदेश पहुंचेगे।

बताया जा रहा है कि 15 हाथियों में से छह हाथी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे और बाकी बचे नौ हाथियों में से कुछ पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे। फिलहाल वन विभाग कर्नाटक से आने वाले नए मेहमानों की मेजबानी की तैयारियों में जुटा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में छह हाथी हैं, कर्नाटक से आने वाले हाथियों के बाद ये संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। वहीं, कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व (मैसूर) के साथ ही तीन स्थानों से यहां पांच और हाथी लाने की बात चल रही है। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं। हाथियों को लाने में करीब पांच लाख रुपये का खर्च आएगा।

कर्नाटक से आ रहे हाथियों का उपयोग सतपुड़ा, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणियों की सुरक्षा में किया जाएगा। कर्नाटक से प्रदेश के लिए कुल 15 हाथी लाने का निर्णय लिया गया है। इस पर विभागीय मुहर के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। इनमें से 15 में से 6 हाथी एसटीआर को मिलेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में धीरे.धीरे वन्यप्राणियों की संख्या में बढोतरी हो रही है। यहां 54 से ज्यादा बाघ हैं। वहीं बारहसिंगा भी काफी तादात में मौजूद हैं। जल्द ही नए हाथी आने के बाद यहां हाथियों की संख्या में इजाफ हो जाएगा।

हर साल होता है हाथी महोत्सव

कर्नाटक से आ रहे हाथियों का उपयोग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अलावा पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणियों की सुरक्षा में किया जाएगा। हाथियों का उपयोग टाइगर रिजर्व में बाघों के रेस्क्यू और पर्यटकों को सैर कराने में भी किया जाता है। रात के वक्त पेट्रोलिंग के लिए भी हाथियों की मदद ली जाती है। हर साल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सात दिवसीय हाथी महोत्सव का भी आयोजडन होता हैए जिसमें हाथियों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिविर का भी आयोजन होता है।

कृषि मेले में आकर्षण का केंद्र बना 10 करोड कीमत का 'गोलू.टू' नाम का भैंसा, सेल्फी की मची होड़

यूपी मेरठ- जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम में तीन दिवसीय कृषि मेले लगा। मेले के पहले दिन दस करोड़ रुपए कीमत का 'गोलू.टू' नाम का भैंसा किसानों के आकर्षण का केंद्र रहा। जिसका वजन 15 क्विंटल है। वहीं, एक साल में उसका सीमन 25 लाख में बिकता है। इतना ही नहीं इसकी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं।

बता दें कि इस दम करोड़ के भैंसे का नाम गोलू है। यह पानीपत हरियाणा से अपने मालिक पद्मश्री सम्मान प्राप्त नरेंद्र सिंह के साथ मेले में पहुंचा। वहीं, भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह बताया कि इस भैंसे की कीमत दस करोड़ तक लग चुकी है। भैंसे के खानपान व देखभाल में प्रति महीने लाखों रुपए का खर्च आता है। साथ ही उन्होंने बताया कि गोलू से काफी आमदनी भी होती है।दरअसल यह भैंसा रोजाना 25 लीटर दूध, 15 किलो फल, 15 किलो दाना, दस किलो मटर और हरा चारा भी खाता है। वहीं, रोजाना शाम को इसे सैर कराने भी ले जाया जाता है। उसके शरीर पर रोजाना तेल के साथ मालिश भी की जाती है। इतना ही नहीं इस भैंसे का स्पर्म बेचकर भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह हर महीने लाखों रुपए की कमाई करते हैं। वहीं, जैसे जैसे भैंसे के चर्चे बढ़ते जा रहे है, इस के स्पर्म की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस की मांग हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में हो रही है।

दस करोड़ के भैंसे को देखते ही मेले में भैंसे के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद लोगों ने भैंसे के साथ सेल्फी लेनी शुरू कर दी और देखते ही देखते भैंसे के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों का तांता लगा गया। इससे पहले कृषि मेले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के करमवीर सिंह का भैंसा युवराज भी पहुंचा था। जिसकी कीमत सवा नौ करोड़ रूपए थी। बता दें कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि कुंभ.2022 का शुभारंभ हुआ। इसमें 150 स्टॉल लगे हैं। वहीं, इसमें भैंसे के साथ उद्योग प्रदर्शनी, काला जादू और डाग शो के केंद्र भी काफी आकर्षक रहे।

आलू-टमाटर के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की गिरावट की आशंका, कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

हलधर किसान।98262 25025- देश में इस बार आलू और टमाटर के उत्पादन में 4 से 5 फीसदी की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहने की संभावना है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के उत्पादन को लेकर पूर्वानुमान जारी किये गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक आलू का उत्पादन 2021.22 में 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ पांच करोड़ 33.9 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसका उत्पादन पांच करोड़ 61.7 लाख टन हुआ था। इस बार टमाटर के उत्पादन में भी 4 फीसदी की कमी हो सकती है।

इस साल टमाटर का उत्पादन दो करोड़ 3.3 लाख टन रह सकता है, जो पिछले साल दो करोड़ 11.8 लाख टन था। हालांकि इस बार प्याज के उत्पादन में भारी इजाफा देखा गया है। इस साल प्याज का उत्पादन तीन करोड़ 12.7 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसका उत्पादन दो करोड़ 66.4 लाख टन हुआ था।

फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा

फलों और सब्जियों के उत्पादन की बात करें, तो इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस साल देश में सब्जियों का उत्पादन 20 करोड़ 48.4 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल में यह 20 करोड़ 4.5 लाख टन दर्ज किया गया है। फलों का उत्पादन 10 करोड़ 72.4 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 10 करोड़ 24.8 लाख टन रिकॉर्ड किया गया था। मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार देश में इस साल बागवानी फसलों के उत्पादन में 2.31 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान है, जिसके चलते इसका उत्पादन 34 करोड़ 23.3 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 33 करोड़ 46 लाख टन दर्ज किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा हर फसल वर्ष को लेकर अलग.अलग समय पर पूर्वानुमान आंकड़े जारी किये जाते हैं।

दवाई कंपनी के खिलाफ किसानों ने दर्ज कराई शिकायत

मानसून के विदा होने के बाद भी चक्रवात की वजह से बस्तर में हो रही बारिश से पहले ही किसान परेशान हैं और उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सोनारपाल इलाके में दवा के छिड़काव से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

दरअसल किसानों ने अपने टमाटर के पौधों में कुछ विकृति देख बायर कंपनी के नेटिवो दवा का छिड़काव किया था, जिसके बाद यह दवा उनके लिए जहर बन गई और टमाटर की खड़ी फसल रातों.रात तबाह हो गई, लगभग 25 किसानों को अपने टमाटर के पौधों में दवा के छिड़काव से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसानों ने भानपुरी थाना में बायर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफलिखित शिकायत दर्ज करवाई है और संबंधित फर्म के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।

कंपनी के लोगों ने दो टूक कह दिया कि उनकी दवा की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता, इधर किसान अपने खेतों में पूरी तरह से मुरझा चुकी टमाटर की फसल देखकर परेशान हैं।

मुरझा गए टमाटर के पौधे

जिस खेत में आमदनी की आस किसानों ने लगा रखी थी अब वहां से उन्हें कोई उम्मीद नहीं जग रही है, बताया जा रहा है कि 25 किसानों के लगभग 150 से अधिक एकड़ में लगाए गए टमाटर के पौधे पूरी तरह से मुरझा के खत्म हो गए जिससे बस्तर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और बाजार में 80 से 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहे है, इधर इस पूरे मामले में बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने इस दवा की हॉर्टिकल्चर के लैब में जांच कराने की बात कही है और अगर दवा में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन किसानों को दिया है।

जूनियर नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता 12 से 25 दिसम्बर तक

हलधर किसान (98262 25025)। भोपालवासी दिसम्बर माह में देश के बेहतरीन घोड़ों के साथ उत्कृष्ट घुड़सवारों को आपस में मुकाबला करते हुए देख सकेंगे। भोपाल स्थित मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में आगामी 12 से 25 दिसम्बर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता.2022 का आयोजन किया जायेगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने विशनखेड़ी स्थित घुड़सवारी अकादमी में प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश भर से 200 खिलाड़ी और 200 घोड़े भाग लेंगे। तेरह दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में शो जंपिंग, क्रॉस कन्ट्री, ड्रेसाज, टेंट पैगिंग के टीम और इंडिविजुअल इवेंट होंगे।

श्रीमती सिंधिया ने समीक्षा के दौरान खिलाड़ियों और उनके घोड़ों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रतियोगिता के मद्देनजर घोड़ों के लिए टेम्परेरी अस्तबल बनाने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने प्रतियोगिता के दौरान हेल्प डेस्क, मेडिकल, परिसर की सुरक्षा, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तथा घुड़सवारी अकादमी की साफसफाई एवं कचरा गाड़ी प्रतिदिन भेजने और पानी की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।

मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के मुख्य प्रशिक्षक कैप्टन श्री भागीरथ प्रसाद ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में 16 राज्यों के घुड़सवार भाग लेंगे। प्रतियोगिता को घुड़सवारी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफसे जूरी और ऑफिशियल जज करेंगे। इस अवसर पर संचालक खेल और युवा कल्याण रवि कुमार गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री कावरे ने जयपुर में आयुर्वेद फार्मेसी लेब का किया निरीक्षण

हलधर किसान। मप्र आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर कावरे ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेद फार्मेसी लेब का निरीक्षण किया। उन्होंने लेब में बनाई जा रही 100 से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को देखा। मंत्री श्री कावरे ने बताया कि मध्यप्रदेश औषधीय पौधों के मामले में काफी समृद्ध है। प्रदेश में आयुष दवाइयों के उत्पादन की बड़ी संभावनाएँ हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये देवारण्य योजना शुरू की है।

राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश का 31 प्रतिशत भू.भाग वन से आच्छादित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन में निवेश करने वाली फार्मेसी कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जायेगी।

आयुष राज्य मंत्री श्री कावरे को फार्मेसी कंपनी के संचालकों द्वारा उत्पादित दवाइयों के मार्केटिंग के संबंध में भी जानकारी दी गई।

मिलन समारोह समाज व परिवार के बीच मिलन की कड़ी होता है : जैन

जैन एग्रो एजेंसी का दीपावली मिलन समारोह रहा यादगार, परिवार सहित शामिल हुआ स्टॉफ

हलधर किसान। 98262 25025 प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्था जैन एग्रो एवं हलधर किसान मासिक समाचार पत्र का दिपावली मिलन समारोह संस्था कार्यालय नूतन नगर खरगोन में समारोहपूर्वक मनाया गया। यहां प्रदेशभर के संस्था से जुड़े ब्रांच संचालकों के साथ ही डीलर एवं स्टॉफ सदस्य परिवार सहित शामिल हुए।

सभी ने मंच से एक दूसरे का परिचय देने के साथ ही दिपावली पर्व की शुभकामना दी।

कार्यक्रम के दौरान संस्था मार्गदर्शक विनोद जैन ने कहा कि जैन एग्रो एजेंसी की शुरुआत बीज भंडार फर्म से छोटे स्तर पर हुई थी, जो आज संचालक विवेक जैन की कड़ी मेहनत से एक वटवृक्ष के समान प्रदेशभर में ब्रांच के माध्यम से फैलाकर प्रतिष्ठित संस्था के रुप में जाना. पहचाना नाम बन गया है। इस संस्था के विकसित होने में स्टॉफ की भी महती भूमिका है, जिन्होंने ईमानदारी, निष्ठा से काम करते हुए संस्था का विश्वास कायम रखा।

संचालक विवेक जैन ने कहा मिलन समारोह समाज व परिवार के बीच मिलन की कड़ी होती है, आज हम व्यवसायिक रुप से नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रुप में इकट्ठा हुए है। व्यापार, व्यवसाय में जोखिम बना रहता है लेकिन सभी मिलकर काम करते है तो यह आसान हो जाता है और संस्था के साथ उससे जुड़े सदस्य निश्चित तरक्की करते है। समाजसेवी जगदीश वानखेड़े ने कहा कि बीज भंडार आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उपलब्ध कराने में बीज भंडार ने किसानों के बीच गहरी पैठ बनाई है, जो उन्हें प्रतिस्पर्धा के इस बाजार से अलग पहचान दिलाती है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी, जोडियों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान सभी ने सामुहिक भोज में व्यंजनों का लुत्फउठाया।

11 नवंबर से मुरैना में लगेगा कृषि मेला नई टेक्नोलॉजी से रुबरु हो सकेंगे किसान

हलधर किसान। मप्र के मुरैना जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में 11, 12 और 13 नवम्बर को तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना सहित अन्य जिलो से लगभग 35 हजार किसानों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेले में आने वाले कृषकों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और नई मशीनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुरैना कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने बताया कि, 11 नवंबर को किसानों को मेला स्थल तक लाने के लिए 255 बसों का, 12 नवंबर के लिए 144 बसों को और 13 नवंबर के लिए 141 बसों का इंतज़ाम किया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय मेले की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना जिले में पहुंचे। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे अधिकारियों को ज़रूरी दिशा.निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि मेला आयोजित कर रहे हैं। मेले में आने वाले किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और नई मशीनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कृषि मेले में प्रदेश और देश से विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप आएंगे। इसके साथ ही इस मेले में खेती में नई टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई जाएगी। वहीं, इस मेले के माध्यम से अंचल के किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा। यह ग्वालियर-चंबल अंचल की किसानों के लिए एक ऐतिहासिक मेले के रूप में होगा और ऐसे अंचल के किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा।

किसानों को न हो असुविधा

अधिकारियों को आदेश देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इस तीन दिवसीय मेले में आने वाले किसानों को असुविधा न हो, इसलिए बसों का मूवमेंट ऐसी जगहों पर किया जाए जिससे सभा स्थल पहुंचने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े मंत्री ने मार्गों पर साइन बोर्ड लगाने के और दूसरे ज़रूरी आदेश अधिकारियों को दिए।

केंद्र ने खाद्यान्नों की एमएसपी बढ़ाई, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा

हलधर किसान। केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)में बढ़ोतरी का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023.24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दलहन (मसूर)के एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्ण उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सरसों की में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं जूट में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 9 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

गेहूं बढ़कर 2125रूपये : मसूर 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा, गेहूं में 110 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। यह अब 2015 रुपये बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य : न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है। ऐसे में सरकार किसानों से जिस भाव पर खाद्यान खरीदती है उसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कहा जाता है। किसी फसल का एमएसपी इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। वर्तमान में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

वर्ष में दो बार तय किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य : सरकार की तरफसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का एलान कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिश पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है।

प्राकृतिक तौर तरीके से लौटी रामचंद्र की भूमि की उर्वरा शक्ति

हलधर किसान। मप्र खरगोन जिले के रजूर गांव के रामचंद्र पाटीदार ने अपनी कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने पर हिम्मत नहीं हारकर, फिर से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का संकल्प लिया और उसमें कामयाब करके दिखाया। पाटीदार अब ऐसे किसानों के लिए प्रेरणा बन गए है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म या क्षीण होने पर खेती से किनारा करने लगे थे। पाटीदार ने बताया मिट्टी में जीवांश के प्रबंधन से भूमि की उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। आज अमरूद की खेती से लाखों की उपज कर अदरक की खेती भी कर रहे है। ये सब उसके लिए इतना आसान नही था।

खेती से सिर्फउपज ही ले जाते है घर : रामचंद्र ने बताया कि खेती से वे सिर्फअनाज या फल सब्जी ही घर ले जाते है। बाकी फसल से निकला अन्य भाग भूमि में ही छोड़ देते है। इसके अलावा खेत में से निकले खरपतवार को उखाड़ कर उसकी बेड बनाकर खेती में जीवांश या उर्वरा शक्ति लौटाने पर हमेशा विचार करते है। साथ ही वे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल छोड़ चुके है। मिट्टी में जीवांश की उपलब्धता के लिए वो न सिर्फवेस्टडिकम्पोजर, गोकृपा अमृतं, जीवामृत, बीजामृत बल्कि इन सब से अलग खेत से सिर्फअनाज या फल ले जाने का काम करता है। बाकी फसलो का आच्छादन पूरा भूमि/ खेत मे ही छोड़ देता है। इसका परिणाम ये हुआ कि कंकरीली मिट्टी में भी बाग सजा पाए है।

बढ़ी एथेनॉल कीमतें, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी हुई बढ़ोत्तरी

केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में हुए अहम फैसले

हलधर किसान। (98262-25025) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा डिस्टिलरीज से खरीदे जाने वाले इथेनॉल की लागत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले में चीनी कंपनियों से जो ऑयल कंपनियां एथेनॉल खरीदती हैं, उनकी कीमतें सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी 2.75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से की गई है।

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल कम करने में मदद मिलेगी और इससे गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी फायदा होगा। कैबिनेट की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी डिस्टिलरी योजना का लाभ उठा सकेंगी और उनमें से बड़ी संख्या में ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति करने की उम्मीद है।

ये हैं नए दाम

सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सी हैवी मोलासेज से इथेनॉल की कीमत 46.66 रुपये से बढ़ाकर 49.41 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। बी हैवी मोलासेज से इथेनॉल की कीमत 59.08 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 60.73 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गन्ने के रस/ चीनी , चीनी के सिरप से इथेनॉल की कीमत 63.45 रुपये से बढ़ाकर 65.61 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और परिवहन शुल्क भी देय होगा।

सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत, तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10 प्रतिशत तक बेचती हैं। वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सरकार ने 2014 से इथेनॉल के प्रशासित मूल्य को अधिसूचित किया है। 2018 के दौरान पहली बार, सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी, जिससे इथेनॉल की आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013.14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़ गई है।

फर्टिलाईजर के भी तय हुए नए दाम

केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि.किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में पोषक तत्व आधारित उर्वरकों की नई दरों को मंजूरी मिल गई है। अब रबी सीजन के लिए किसानों को सस्ती और रियायती दरों पर ये उर्वरक उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 51875 करोड़ रुपये की सब्सिडी पर मुहर लगा दी है। बता दें कि इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिये मान्य किया गया है।

ये हैं नये दाम

केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ;सीसीईएद्ध ने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश समेत कई न्यूट्रिएंड बेस्ड उर्वरकों के प्रति किलोग्राम के आधार पर नई दरों को मंजूर कर लिया है। इस आधार पर ये हैं उर्वरकों के नये दाम.नाइट्रोजन . 98.02 रुपये ;प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस . 66.93 रुपये (प्रति किलोग्राम), पोटाश . 23. 65 रुपये प्रति किलोग्राम, सल्फर . 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम

हरियाणा के चौधरी सॉल्वेंट प्लांट ने उठाया सराहनीय कदम, लाखों की पराली खरीदकर बना रहा तेल

हलधर किसान। हरियाणा राज्य के टोहाना शहर के मनियाना रोड स्थित चौधरी सॉल्वेंट प्लांट द्वारा लाखों रुपए की पराली खरीदकर बॉयलर में प्रयोग करने के बाद चावल का तेल बनाया जा रहा है। चौधरी सॉल्वेंट प्लांट के प्रवीण चौधरी ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से किसानों से पराली खरीदते आ रहे हैं। पहले साल पांच हजार क्विंटल, दूसरे साल 15 हजार क्विंटल तो इस बार 30 हजार क्विंटल पराली की खरीद कर चुके है। पराली को जलाने हेतू अलग से मशीने लगाई जाती है, जिसकी लागत करीबन 20 लाख रूपए आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि अन्य प्लांट धारक भी पराली खरीद सके।

प्रवीण चौधरी ने बताया कि वे हर बार लाखों रुपए की पराली खरीदकर स्टॉक करते है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता है। अगर कोई घटना हो जाती तो नुकसान का सामना उन्हें ही करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाता है और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन व्यापारी को मदद नहीं दी जाती है। सरकार अगर मिलर व सॉलवेंट संचालक को आर्थिक मदद करे तो किसानों को पराली के उचित दाम मिल जाएंगे, जिससे वे पराली को आग नहीं लगाएंगे।

कृषि विभाग के एसडीओ मुकेश मेहला ने कहा कि चंडीगढ रोड स्थित चौधरी सॉल्वेंट प्लांट में पराली की खरीद करके सराहनीय काम किया जा रहा है। किसानों से यह अपील है कि आग लगाने की बजाय उसे बेचकर अपनी लाभ कमाए। इस कदम को उठाने के लिए प्रवीण चौधरी को सम्मानित किया जाएगा।

फसल अवशेषों को जलाने पर बने 288 चालान

हरियाणा, कुरुक्षेत्र। हरसेक के माध्यम से 244 और अन्य 133 माध्यमों से 377 जगहों पर फसल अवशेषों में आग लगाने की सूचनाएं प्राप्त हुई। इन सूचनाओं के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो 290 जगहों पर फसल अवशेषों में आग लगाने की पुष्टि हुई और 87 जगहों का पता नहीं लग पाया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल किसानों को सरकार की योजना के प्रति जागरुक किया और साथ में ही 288 लोगों का चालान कर 6 लाख 97 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की प्रगति रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र के किसानों को लगातार फसल अवशेष प्रबंधन करके सरकार की योजना का लाभ लेने तथा फसल अवशेषों में आग न लगाने के प्रति लगातार जागरुक किया जा रहा है।

इन प्रयासों के बावजूद जिन लोगों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है, उनके खिलाफसख्त कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर सरकार द्वारा 878 किसानों के खाते में 66 लाख 95 हजार 140 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इन किसानों ने 6695.14 एकड़ जमीन के फसल अवशेषों के बेलर बनाए। इन किसानों को बेलर बनाने पर सरकार के नियमानुसार 1 हजार रुपए प्रति एकड़ मुहैया करवाए जाएंगे।

कपड़ा निर्यात को 5 साल में 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य: मंत्री गोयल

हलधर किसान। 98262 25025- नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच.छह वर्षों के देश के कपड़ा निर्यात को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का इरादा है। इस लक्ष्य के पूरा होने पर कपड़ा उद्योग का कुल मूल्य बढ़कर 250 अरब डॉलर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021.22 में भारत के कपड़ा उद्योग ने करीब 42 अरब डॉलर का निर्यात किया था।

निर्यात संवर्द्धन परिषदों के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि विनिर्माताओं को मांग पूरी करने के लिए कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कपास उद्योग से जुड़े सभी पक्षों को कपास से बने उत्पादों का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करने भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कपड़ा निर्यात करीब 42 अरब डॉलर का रहा था और अगले पांच.छह साल में इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गोयल ने कहा कि कपड़ा निर्यात के इस लक्ष्य को अगर हासिल कर लिया जाता है तो इस उद्योग का कुल घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य सम्मिलित रूप से 250 अरब डॉलर का हो जाएगा।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कपास का उत्पादन फसल सत्र 2022.23 के दौरान 3.41 गांठ रहने का अनुमान है जबकि एक साल पहले यह 3.12 गांठ रहा था। एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम का होता है। कपास की बुवाई खरीफ सत्र में होती है और अक्टूबर से इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। गोयल ने कहा कि कपड़ा मिशन के तहत उपलब्ध कोष का इस्तेमाल नई परियोजनाओं में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी.20 बैठकों एवं कार्यक्रमों के दौरान भी भारतीय कपड़ा क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं के बीच बीत रहा है साल 2022, बीते नौ माह में लगभग रोजाना हुई दुर्घटना

पिछले नौ माह में 2.755 लोगों की मृत्य, 18 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित, 4 लाख घर नष्ट, 70 हजार से मवेशियों की मौतें हुईं

हलधर किसान। 98262 25025
देश में 2022 का साल भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड जैसी अनेक प्राकृतिक घटनाओं से भरा रहा है। बीते नौ महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब देश के किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो। यह जानकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की नई रिपोर्ट से सामने आई है। सीएसई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में इस साल 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 273 दिनों में से 242 दिनों में किसी न किसी तरह की प्राकृतिक घटनाएं दर्ज की गई है। जिसमें हीटवेव, शीत लहर, चक्रवात, बिजली, भारी वर्षा, बाढ़ और लैंड स्लाइड की घटनाएं शामिल है।

भारत में लोगों ने वर्ष 2022 के नौ माहों में लगभग प्रतिदिन किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा को झेला है। और इसी का नतीजा है कि इस दौरान 2.755 लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं इस दरमियान 18 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और 4 लाख घर नष्ट हुए जबकि लगभग 70.000 पशु मारे गए। यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा किए गए एक नए आकलन में सामने आया है। यह अतिविषम मौसमी चरम घटनाएं 1 जनवरी से 30 सितंबरए 2022 के बीच दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट को जारी करते हुए सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहाए ग्रेटा ने 2022 में अभी तक जो कुछ भी देखा है, वह तेजी से गर्म होती दुनिया में नया असामान्य है। जो अतिविषम घटनाएं हम देख रहे हैंए, उसकी तीव्रता और बार.बार होने की प्रक्रिया में वृद्धि होते हुए भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अतिविषम मौसम की घटनाओं और उनसे जुड़े नुकसान और क्षति पर मौसमवार, महीनेवार और क्षेत्रवार विश्लेषण उपलब्ध कराती है। यह भारत में अतिविषम मौसम की घटनाओं की तीव्रता और उसके भूगोल पर एक साक्ष्य आधार भी तैयार करने का प्रयास है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय पर जो आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, वह अपूर्ण हैं और पूरी तस्वीर पेश नहीं करते।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 के नौ माह में भारत ने प्रतिदिन एक आपदा झेली। इसमें गर्म और सर्द हवाओं से लेकर चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं शामिल थीं। रिपोर्ट तैयार करने वालों में से एक रजित सेनगुप्ता कहते हैं कि इन आपदाओं में 2.755 जानें गई, 18 लाख हैक्टेयर फसल का क्षेत्र प्रभावित हुआ, 4.16. 667 से अधिक घर नष्ट हुए, लगभग 70.000 पशु मारे गए।

यही नहीं उनका कहना था कि यह नुकसान और क्षति का जो आंकलन किया गया है उसे संभवतः कम करके आंका गया है क्योंकि हर घटना के आंकड़े विस्तृत रूप् से एकत्रित नहीं किए गए हैं। आपदाओं के हर दूसरे दिन होने वाली घटना के मामले में मध्य प्रदेश में ऐसे दिनों की संख्या अधिक थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 359 लोगों की मौतें हुई। मध्य प्रदेश और असम दोनों में एक सामान 301 लोगों की मौतें हुई। मध्य प्रदेश में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी फसल क्षेत्र के नुकसान की सूचना दर्ज नहीं है। भारत ने 1901 के बाद से 2022 में अपना सातवां सबसे नम जनवरी माह दर्ज किया। मार्च भी 121 वर्ष में अब तक का सबसे गर्म और तीसरा सबसे सूखा रहा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत ने 121 वर्षों में सबसे गर्म और सबसे शुष्क जुलाई देखा। इस क्षेत्र ने 2022 में अपना दूसरा सबसे गर्म अगस्त और चौथा सबसे गर्म सितंबर भी दर्ज किया। देश के 30 राज्यों में आकाशीय बिजली और तूफान से 773 लोगों की जानें गई।

इसी प्रकार से मानसून के तीन माह जून से अगस्त तक के प्रत्येक दिन देश के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक वर्षा होने के संकेत मिले हैं। यही कारण है कि बाढ़ की तबाही ने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए असम का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था, जिससे जानमाल और आजीविका का भारी नुकसान हुआ।

बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता

नारायण ने बताया कि यही कारण है कि सीएसई द्वारा तैयार अतिविषम मौसम रिपोर्ट कार्ड को समझना महत्वपूर्ण है। वह कहती हैं कि यह रिपोर्ट इन अतिविषम घटनाओं के प्रबंधन के लिए बहुत कुछ करने की बात करती है। हमें जोखिम को कम करने और लचीलेपन में सुधार करने के लिए आपदा के प्रबंधन से आगे बढ़ना होगा। यही कारण है कि हमें बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रणालियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। वह कहती हैं कि यह रिपोर्ट उन देशों से नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करने की आवश्यकता की भी बात करती है जिन्होंने वातावरण में उत्सर्जन का योगदान दिया और इस क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करने वाले मॉडल स्पष्ट करते हैं कि अतिविषम मौसम की घटनाएं बार.बार होंगी और इनकी तीव्रता में वृद्धि होगी। यह रिपोर्ट कार्ड अच्छी खबर नहीं है लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत है ताकि हम प्रकृति के प्रतिशोध को समझ सकें जो हम आज देख रहे हैं और यह भी समझें कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के साथ उस पैमाने पर मुकाबला नहीं करते हैं जिसकी अभी जरूरत है, तो कल यह और बदतर हो जाएगा।

लू ने ली 45 लोगों की जान

लू ने 45 लोगों की जान ले लीं, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं है, यह उत्तर भारत में लोगों पर लंबे समय तक उच्च तापमान का प्रभाव है। किसानों से लेकर श्रमिकों ने भीषण गर्मी का सामना किया। अच्छी खबर यह है कि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्य कम थी। देश में 95.066 हेक्टेयर क्षेत्रों को नष्ट करने वाले चक्रवातों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल दो लोगों की जानें गईं। नारायण ने कहा कि यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा चक्रवात की भविष्यवाणी पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के कारण संभव हुआ है जिससे राज्य सरकारों को पर्याप्त चेतावनी दी जा सके। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि राज्य सरकारें, विशेषकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने आपदा प्रबंधन की अपनी प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किया है। वह कहती हैं कि यह स्पष्ट है कि अब इन घटनाओं की तीव्रता और सिर्फआपदाओं को ही गिनने की जरूरत नहीं है, इससे होने वाले नुकसान और क्षति पर विश्वसनीय आंकड़ों की भी बहुत अधिक आवश्यकता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओ ने 350 बोरियों से बनाया बोरी बंधान

हलधर किसान। 98262 25025
खरगोन में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड भगवानपुरा द्वारा मध्यप्रदेश स्थापना पखवाड़े के उपलक्ष्य में जल संरक्षण, नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, स्वच्छता, खेल प्रतियोगिता व शासन की योजनाओं के तहत अभियान प्रस्फुटन समितियों व नव अंकुर संस्थाओं सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम के छात्र.छात्राओं के माध्यम से भगवानपुरा ब्लॉक के भगवानपुरा, बहादरपुरा, पीपलझोपा, सरवर देवला, गड़ी पांचों सेक्टर में कार्य संपादित किये जा रहे है।

विकासखंड के समन्वयक महेश कुमार खराड़े के मार्गदर्शन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताए स्वाध्याय परिवार से सुखदेव राठौड़, सुरेश माली, सचिन राठौड़, धीरज मालवीया, नवांकुर संस्थाओं से भगवानपुरा सेक्टर दिनेश महाजन, बहादरपुरा सेक्टर कृष्णकांत जायसवाल, गड़ी सेक्टर राजेन्द्र ठाकुर, नया बिलवा से डोंगरसिंह वास्कले, धुलकोट प्रस्फुटन समिति से अध्यक्ष ओमप्रकाश सेन, भगवानपुरा नगर विकास समिति से सुनील जाधव, सुरेश महाजन, योगेश गोपाल, रंजीत अवचरे सभी का उत्साहवर्धन किया। भगवानपुरा सरपंच ज्ञानसिंह डावर आदि ने जल संरक्षण का संकल्प लेकर आगामी जल संकट से बचने के लिए जल है तो जीवन है इस कड़ी में 350 बोरियों का बंधान खोखली माता मंदिर पर बनाया गया। अभी प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से 32 बंधान अन्य अन्य ग्रामों में बना दिए गए। आगामी दिनों में ब्लॉक में 100 बोरी बंधान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।